(c) A scheme for rehabilitation of the deep sea fishing sector was announced by the Government in April, 1991 which was further liberalised in June, 1992. The scheme contains reliefs such as waiver of penal interest and reschedulement of debt over the balance economic life of the vessels.

In addition to this, following steps have been taken to assist the deep sea finishing sector: —

(i) Provision of 33% subsidy on the cost of indigenously constructed deep sea fishing vessels.

(ii.) Provision of loan facility on soft terms by SCIC1 Limited.

(iii) Assistance for construction of fishing harbours at major and minor ports.

(iv) Training of deep sea fishing operatives for manning the fishing vessels.

'v) Assistance for diversified fishing.

(vi) Price reimbursement on HSD consumed by Export Oriented deep sea fishing vessels.

(vii) Equity participation by Marine Products Export Development Authority in deep sea fishing projects.

Extension of tenure to Murari Committee

2815. SHRI MENTAY PADMAN - BHAM: Will the Minister of FOOD PROCESSING INDUSTRIES be pleased to state:

(a) what is the number of extensions of tenure granted to the Murari Committee on rehabilitation of sick deep-sea fishing units;

(b) whether any interim recommen dation has been given by the Murari Committee: and

(c) if so, what are the details there of?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF FOOD PROCESSING INDUSTRIES (SHRI TARUN GOGOI), (a) Four extensions of tenure of three months, three months, one, month and twenty.one days respectively have been granted to the Murari Committee on rehabilitation of sick deep sea fishing units.

lb) No, Sir.

(c) Does not arise.

India's share of processed food in global market

2816. SHRI BHUPINDER SINGH MANN: Will the Minister of FOOD PROCESSING INDUSTRIES be plea-sed to state:

(a) what is India's share of pro. cessed food in the global market the details thereof for the last three years and its share to the total exports of India:

(b) what share of processed food was constituted by the food processed through agricultural produce and its
share to the total exports of processed food;

(f) what is the share of processed food used within the country and its ratio with exports; and

(d) stops to be taken by Government to step up exports of processed food formed by agriculture?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF FOOD PROCESSING INDUSTRIES (SHRI TARUN GOGOI): (a) to (d) Information is being collected and will be laid on the Table of the House.

खाद्य प्रसंस्करण प्रशिक्षण केन्द्र

2817. डा० जिनेन्द्र कुमार जैन :
श्री राम जेठमलानी :

क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की जानकारी

का अधिकतम प्रसार करने के लिए देश में खाद्य प्रसंस्करण प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित किए हैं ;

(ख) यदि हां, तो इस खाद्य प्रसंस्करण प्रशिक्षण केन्द्रों के बारे में ब्यौरा क्या है ;

(ग) जनवरी, 1994 के अंत तक देश के किस-किस राज्य में ऐसे कितने-कितने केन्द्र स्थापित किए जा चुके हैं और आठवीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक ऐसे कितने प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है ;

(घ) आठवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान इन केन्द्रों की स्थापना पर सरकार द्वारा कुल कितनी धनराशि व्यय किए जाने का प्रस्ताव है ; और

(ङ.) इस अवधि के पूरा हो जाने पर इन केन्द्रों में खाद्य प्रसंस्करण कला में प्रति वर्ष कुल कितने युवकों द्वारा प्रशिक्षण प्राप्त कर लिए जाने की संभावना है ?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरुण गोगोई) : (क) से (ङ.) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय स्वयं खाद्य प्रसंस्करण प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना नहीं करता । तथापि मंत्रालय द्वारा एक योजना स्कीम लागू की जा रही है जिसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों में उक्त केन्द्रों की स्थापना के लिए सहायता उपलब्ध कराई जाती है । योजना के अंतर्गत गुणवत्ता परीक्षण उपकरणों सहित संयंत्र और उपकरणों की लागत को पूरा करने के लिए 2.00 लाख रु. तक का सहायता अनुदान दिया जाता है । योजना के अंतर्गत वाणिज्यिक उत्पादन के लिए मूल धनराशि/आवर्ती निधि के रूप में प्रत्येक केंद्र को एक बार अधिकतम 1.00 लाख रु० दिए जाते हैं । योजना का उद्देश्य ग्रामीणों को उपयुक्त प्रौद्योगिकी के साथ लघु खाद्य प्रसंस्करण यूनिटों को चलाने और उनकी प्रबंध व्यवस्था करने का "प्रत्यक्ष" प्रशिक्षण देना है । 1992-93 में शुरू हुई आठवीं पंचवर्षीय योजना से लेकर जनवरी, 1994 तक 43 खाद्य प्रसंस्करण प्रशिक्षण केंद्रों की स्थापना के लिए सहायता दी जा चुकी है । उनका राज्यवार ब्यौरा निम्नलिखित है :—

बिहार . . .	3
हरियाणा . . .	2
हिमाचल प्रदेश . .	1
कर्नाटक . . .	3
मिजोरम . . .	6
तमिलनाडु . . .	1
उत्तर प्रदेश . .	19
प० बंगाल . .	8
कुल	43

इनमें से 15 केंद्रों की स्थापना की जा चुकी है और शेष 28 केंद्र कार्यान्वयन के विभिन्न चरण पर हैं और आशा है कि वे जल्दी ही काम करना शुरू कर देंगे । इसके अलावा, हाल में ऐसे और 74 केंद्रों को स्थापित करने के लिए मंजूरी दी गई है और आशा है कि 1994 के अंत तक इनकी स्थापना हो जाएगी । आठवीं योजना के दौरान ऐसे 250 केंद्रों को 7.5 करोड़ रु० तक की सहायता उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है । आशा है कि आठवीं योजना के दौरान इन प्रशिक्षण केंद्रों के मार्फत लगभग 30,000 युवक प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे ।

Joint Venture proposals in deep sea fishing

2818. SHRI AJIT P. K. JOGI:
SHRI MOOLCHAND MEENA;

Will the Minister of FOOD PROCESSING INDUSTRIES be pleased to state;

(a) whether any Committee has been constituted by Government to look into Joint venture proposals in deep sea fishing;

(b) if so, the number of proposals cleared by the Committee during the current financial year;